भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2570
दिनांक 17 **मार्च**, 2022

जैव-शोधनशाला

†2570.**श्री बी.वाई. राघवेन्द्र**:
श्री एस. मुनिस्वामी:
डॉ. उमेशजी. जाधव:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इथेनॉल मिश्रण के लिए देश में जैव-शोधनशालाओं की स्थापना के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इथेनॉल मिश्रण के संबंध में कुछ राज्यों की आशंकाओं पर ध्यान दिया है और उनका समाधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस पर देश की आयात निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सरकार ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर देश में पेट्रो रसायन रूट सहित सेल्यूलॉसिक और लिग्नो-सेल्यूलॉसिक से दूसरी पीढ़ी (2जी) एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री जी-वन योजना (पीएमजेवाई) को अधिसूचित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय तेल उद्यम (सीपीएसईज) देश में दूसरी पीढ़ी (2जी) की एथेनॉल जैव रिफाइनरियों की स्थापना कर रहे हैं जो हरियाणा के पानीपत, पंजाब में भठिण्डा, ओडिशा में बारगढ़, असम में नुमालीगढ़ तथा एक प्रदर्शन परियोजना पानीपत में है।

(ख): देश में एथेनॉल उपलब्धता के कमी वाले राज्यों में एथेनॉल उपलब्धता बढ़ाने के लिए, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की

कमी वाले राज्यों में समर्पित एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की थी। ईओआई के आधार पर, ओएमसीज ने एथेनॉल की कमी वाले इन राज्यों में 131 बोलीदाताओं के साथ दीर्घावधिक आफटेक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा किसानों की आय बढ़ेगी।

(ग): तेल और प्राकृतिक गैस पर आयात निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए गए उपायों में गुणवत्ता वाले भू-वैज्ञानिक आंकड़ों का सृजन और इनकी सहज उपलब्धता, नए अन्वेषण रकबे प्रदान करना, विकसित नए रकबों से उत्पादन में तेजी लाना, मौजूदा उत्पादक रकबों से उत्पादन की अधिकतम करने पर ध्यान देकर घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में वृ के लिए कई नीतिगत पहलें शामिल हैं। सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 की अधिसूचना द्वारा देश में जैवईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। इस नीति में पेट्रोल में मिश्रण हेतु एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने हेतु जैव-एथेनॉल के उत्पादन के लिए एक से अधिक फीडस्टॉकों के उपयोग की अनुमति है। प्रधान मंत्री जी-वन योजना इस नीति की पूरक है। एथेनॉल के आपूर्ति पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के चलते सरकार ने देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 के बजाय 2025-26 में हासिल करने का निर्णय लिया है।

***